

सम्पादकीय

वाम राजनीति की नयी उम्मीद : एमए बेबी

कई चुनौतियों के बीच केरल के वरिष्ठ साम्यवादी नेता मरियम एलेक्जेंडर बेबी को देश के सबसे बड़े वामपंथी दल- काय्यनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्किंस्ट) ने रविवार को अपना नया महासचिव नियुक्त किया। पिछले वर्ष 12 सितंबर को सीताराम येचुरी के निधन के बाद से यह पद रिक्त था जो उहने लगभग 9 साल तक सम्हाला था। तमिलनाडु के मदुरै में सम्पन्न पार्टी के 5 दिवसीय सम्मेलन के अंतिम दिन उन्हें यह पद दिया गया। उनके खिलाफ खड़े महाराष्ट्र के ट्रेड यूनियन नेता डीएल कराड के सिर्फ 31 वोट मिले। सीपीआई (एम) की केरल शाखा से पार्टी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद सम्हालने वाले वे दूसरे नेता हैं- दिग्गज इंडिया-एस-नंबुदीरीपाद के पश्चात। पार्टी द्वारा हाल ही में 75 साल की उम्र सीमा के नियम लागू करने के बाद पूर्व महासचिव प्रकाश करात, बृद्ध करात, सुर्यकांत मिश्रा, सुभाषिनी अली, माणिक सरकार और जी. रामकृष्णन जैसे वरिष्ठ नेता पोलिट ब्यूरो से बाहर हो गये थे। केवल 79 वर्षीय केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को रणनीतिक कारणों से रखा गया है पोलिट ब्यूरो में 8 नए सदस्य शामिल हुए, वे हैं- त्रिपुरा विधानसभा में विपक्ष के नेता जितेंद्र चौधरी, तमिलनाडु के पूर्व सीपीएम सचिव के बालाकृष्णन व ट्रेड यूनियन नेता यू. वासुकी, सीकर (राजस्थान) के सांसद अमरा राम, श्रीदोष भट्टाचार्य (पश्चिम बंगाल), अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव विजू कृष्णन, अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ की महासचिव मरियम धावले और पूर्व छात्र नेता आर. अरुण कुमार। येचुरी के मुकाबले बेबी को वैचारिकी के स्तर पर अनुदान नेता माना जाता है। छात्र राजनीति (स्टॉडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया) से मुख्य धारा की राजनीति में आने वाले बैबी को आपातकाल में छात्रों व युवाओं को संगठित करने के कारण जेल भी जाना पड़ा था। वे केरल के शिक्षा मंत्री रहे तथा लोकसभा सदस्य भी रहे। वे ऐसे वर्क में पार्टी के यह अहम पद सम्हाल रहे हैं जब कई तरह की चुनौतियां सामने हैं। ये चुनौतियां संगठनात्मक हैं तो वहीं विधानसभा-लोकसभा में घटते प्रतिनिधित्व भी। इसके साथ ही राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक मौर्चों पर उसका कम होता हस्तक्षेप भी दल के लिये चिंता का विषय है। पिछले 11 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से दक्षिणपंथी विचारधारा को देश भर में फैलाया है, उसका माकूल जवाब देने में वामपंथी दल लगातार नाकाम साबित हो रहे हैं। ऐसा कैवल सीपीएम ही नहीं वरन् देश के दूसरे बड़े साम्यवादी दल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीआई) के बारे में भी कहा जा सकता है। फिर, दोनों दलों के बीच एकता की आशा तो दूर, अब देखना होगा कि क्या तालमेल भी सम्भव है। जो वाम मोर्चा 2004 में बनी कांग्रेस प्रणीत यूपीएसरकार के दौरान मौजूद था, वह अब अस्तित्व में इसलिये भी नहीं है क्योंकि संसद में उसकी उपस्थिति क्षीण है। याद हो कि 2004 में इसे 44 सीटें मिली थीं आज वह 4 पर सिमटी हुई है। इनमें भी तीन उसे सहयोगी दलों के सहयोग से हासिल हो सकीं। पश्चिम बंगाल में लगभग तीन दशक तक सरकार चलाने के बाद वहां तृणमूल कांग्रेस व भजपा ने उसका पूर्ण सफलता कर रखा है।

मोदी और ट्रम्प बहुत बड़ी भूल करने में भी एक समान

- के रवींद्र

सयुक्त राज्य अमरका म, अमरका फस्ट के लिए ट्रम्प के जलदबाजी के प्रयास ने पहले ही भविष्य की परेशानी के बीज बो दिये हैं। दोनों नेताओं ने लोगों के जीवन और आजीविका के साथ जुआ खेला है, और जब चीजें गलत होती हैं, तो वे वास्तविकता का सामना करने के बजाय कहानी को फिर से लिखना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प और नरेंद्र मोदी एक-दूसरे के लिए प्रशंसा व्यक्त करते नहीं थकते। उनका परस्पर सम्मान एक अजीब अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक सौहार्द का आभास देता है, जो निर्विवाद है। जो चीज उन्हें जोड़ती है, वह केवल साझी विचारधारा नहीं है, बल्कि लोकलभावनवाद कथित देशभक्ति और याजना के साथ घाषत - न भारत का 86 प्रतिशत मुद्रा को रातोंरात अमान्य कर दिया। यह कथित तौर पर काले धन, नकली मुद्रा और आतंकवाद के वित्तपोषण को जड़ से खत्म करने के लिए बनाया गया था, लेकिन यह जल्दी ही अराजकता में बदल गया। छोटे व्यवसाय ध्वस्त हो गये, मजदूरों ने शहरों से पलायन कर लिया और एटीएम के बाहर लंबी कतारें आर्थिक कुप्रबंधन का भयावह प्रतीक बन गयीं। विशेषज्ञों द्वारा खतरे की घटी बजाये जाने के बावजूद, मोदी ने अपना मसीहावादी लहजा बरकरार रखा और नागरिकों से उज्ज्वल भविष्य के लिए मात्र 50 दिन की कठिनाई सहने का आग्रह किया।

लाकरुमानपाद, कायदा दस्तावेज, और प्रायः नाटकीय परन्तु लापरवाह निर्णय लेने की प्रवृत्ति से आकार लेने वाला एक समान विश्वास्ति है।

मोदी का 'आत्मनिर्भर भारत', एक मजबूत राष्ट्रवादी झुकाव के साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता का आहान है, जो ट्रम्प के 'अमेरिका फर्स्ट' बयानबाजी को दर्शाता है। दोनों नेता एक ऐसा दृष्टिकोण पेश करते हैं जो राष्ट्रीय गौरव के लिए एक भावनात्मक, लगभग नाटकीय अपील से अपनी शक्ति प्राप्त करता है, जो स्वायतता और शक्ति के भ्रम से घिर हुआ है।

दोनों ही राष्ट्रीय नीति को व्यक्तिगत धर्मयुद्ध के रूप में पुनः ब्रांड करने में माहिर हैं, फिर भी छाती पीटने वाली इस सतह के नीचे स्तर के शासन में एक पैटर्न छिपा हुआ है जो कि सार से अधिक दिखावे से और रणनीति से अधिक भावना से चिह्नित है।

इस संबंध में, ट्रम्प की 'मुक्ति दिवस' पहल मोदी के विमुद्रीकरण प्रयोग से एक अजीब समानता रखती है- एक भयावह गलत अनुमान जो मास्टर स्ट्रोक के रूप में प्रचल्न है। 2016 में मोदी के तहन का जाग्रह किया। डोनाल्ड ट्रम्प के तथाकथित मुक्ति दिवस, व्यापक टैरिफ के एक नये दौर की नाटकीय शुरूआत, ठीक उसी तरह के वैश्विक व्यवधान के साथ हुई है, जिसके बारे में आलोचकों ने चेतावनी दी थी। बाजार की प्रतिक्रियाएं तत्काल और क्रूर थीं। घोषणा के बाद पहले कुछ दिनों में यू.एस. स्टॉक इंडेक्स में तेजी से गिरावट आयी, जिसमें डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज-800 से अधिक अंक गिर गया और नसदक को और भी ज्यादा झटका लगा। अनिश्चितता में अचानक वृद्धि से निवेशक पीछे हट गये, आपूर्ति श्रृंखला एक बार फिर से क्रॉसहेयर में आ गयी और मुद्रास्फीति की आशंका फिर से भड़क गयी। टैरिफ युद्ध ने वैश्विक व्यापार के मूल में प्रहर किया है, जो अमेरिकी आर्थिक संप्रभुता को पुनः प्राप्त करने की आड़ में चीन, यूरोपीय संघ और मैक्सिको सहित प्रमुख आर्थिक भागीदारों से आयात को लक्षित करता है। ट्रम्प ने साहस दिखाना जारी रखा है, यह आशासन देते हुए कि यह समस्या अस्थायी है, ठीक वैसे ही जैसे मोदी ने किया था जब उनका परिवर्तन यद्यप्य स्वस्था के लिए घटकाओं लगभग रातोंरात अंधकारमय हो गया है और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 'बढ़ते व्यापार तनाव और वैश्विक अनिश्चितता' के हवाला देते हुए विकास पूर्वानुमानों को संशोधित किया है। उभयते बाजार, जे निर्यात और आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण पर बहुत अधिक निर्भर हैं, आगे कर्म अस्थिरता के लिए तैयार हैं। अर्थास्त्रियों ने चेतावनी दी है कि निरंतर टैरिफ वृद्धि अगले वर्ष वैश्विक जीडीपी वृद्धि से पूर्ण प्रतिशत अंक कम कर सकती है। जिस तरह मोदी के विमुद्रीकरण में एक भव्य राष्ट्रवादी हस्तक्षेप के सभी लक्षण थे- सिस्टम को साफ करना, भ्रष्टाचार के जड़ से खत्म करना, अर्थव्यवस्था के शुद्ध करना - ट्रम्प का लिबरेशन डे युद्ध जीत की भाषा में लिपटा हुआ था, और अमेरिकी दृढ़ता को प्रतिबिंबित करता था, फिर भी दोनों ही बहुत अवैज्ञानिक थे आंकड़ों के यथार्थ से कटे हुए थे, और संस्थागत परामर्श से रहित थे। संयुक्त राज्य अमेरिका में, अमेरिका फस्ट के लिए ट्रम्प के जलदबाजी के प्रयास ने पहले ही भविष्य की परेशानी के बीज बो

दिये हैं। दोनों नेताओं ने लोगों के जीवन और आजीविका के साथ जुआ खेला है, और जब चीजें गलत होती हैं, तो वे वास्तविकता का समाना करने के बजाय कहानी को फिर से लिखना चाहते हैं। एक गहरी, अधिक परेशान करने वाली समानता भी है - व्यक्तित्व का पंथ जो दोनों पुरुषों को जवाबदेही से बचाता है। मोदी और ट्रंप ने राष्ट्रीय मानस में अपने निजी ब्रांड इतने मजबूत कर लिए हैं कि उनके समर्थक अक्सर आलोचना को विश्वासघात के रूप में देखते हैं। भारत में, कई लोगों ने अराजकता को एक महान उद्देश्य के लिए आवश्यक दर्द के रूप में देखा, भले ही उद्देश्य को कभी स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया हो। अमेरिका में, ट्रंप का 'मुक्ति दिवस' ट्रंप के मूर्ख दिवस के रूप में शुरू हुआ है। कोई यह तर्क दे सकता है कि विमुद्रीकरण और मुक्ति दिवस दोनों ही एक विशेष प्रकार की राजनीति की परिणति का प्रतिनिधित्व करते हैं - एक ऐसी राजनीति जिसमें भावनाएं तर्क पर हावी हो जाती हैं, जहां नारे रणनीति की जगह ले लेते हैं, और जहां अल्पकालिक दृष्टिकोण दीर्घकालिक परिणामों पर हावी हो जाते हैं। इस दुनिया में, नेताओं से परिणाम देने की अपेक्षा नहीं की जाती, बल्कि केवल इरादे को नाटकीय बनाने की अपेक्षा की जाती है। मोदी और ट्रंप, अपने सभी मतभेदों के बावजूद, इस भावनात्मक लोकप्रियता के वास्तुकार हैं,

जो उपलब्धियों से नहीं बल्कि सतत टकराव, निर्मित संकटों और निर्णायिक नेतृत्व के भ्रम से राजनीतिक वैधता के निर्माण करते हैं।

त्रासदी यह है कि इन नाटकीय भूलों से सबसे अधिक पीड़ित लोग सबसे कमजोर हैं। भारत में, दैनिक बेतन भोगी, छोटे व्यापारी और ग्रामीण समुदाय विमुद्रीकरण के दुष्परिणामों का सामना कर रहे हैं कि अमेरिका में, फ्रंटलाइन वर्कर्स, गिरावंश इकॉनामी प्रतिभागी और हाशिए पर पड़े समुदाय सबसे ज्यादा पीड़ित होंगे। फिर भी, मोदी और ट्रम्प द्वारा गढ़े गए राजनीतिक आख्यान इन कष्टों के देशभक्तिपूर्ण बलिदान में बदल देंगे। कठिनाई को नीति विफलता के बजाय राष्ट्रीय शक्ति के प्रमाण के रूप में पेश करेंगे। संस्थानों और विशेषज्ञों के लिए एक साझा तिरस्कार भी है - सत्तावार्दी लोकतुभावनवाद की एक पहचान। मोदी ने अपने विमुद्रीकरण कदम में भारतीय रिंजर बैंक को दरकिनार कर दिया, और ट्रम्प ने नियमित रूप से अपने अधिकारियों को बखास्त कर दिया या चुप करा दिया संस्थानों को कमजोर करना आकस्मिक नहीं है - यह उनकी शक्ति का केंद्र है दोनों नेता 'हम बनाम वे' की गतिशीलता बनाना में सफल होते हैं, जहां संस्थानों के एक पुरानी, अप्रभावी व्यवस्था के अवशेष के रूप में पेश किया जाता है, और नेता लोगों की एकमात्र सच्ची आवाज के रूप में उभरता है।

अहमदाबाद अधिवेशन : कांग्रेस के लिए चुनौती भी अवसर भी !

- शकील अख्तर

अहमदाबाद में होना चाहिए और उसका हल निकलना चाहिए। वहाँ पहले दिन 8 अप्रैल को कांग्रेस वर्किंग कमेटी पार्टी की सर्वोच्च नीतिका निर्धारक ईकाई (सीडब्ल्यूसी) की ही मीटिंग है। याद रखना चाहिए कि इससे पहले की दो सीडब्ल्यूसी की मीटिंग दिल्ली और बेलगावी में अध्यक्ष खरगे ने पार्टी की अन्दरूनी समस्याओं की गहरी पड़ताल की और जितनी सुना सकते थे उतनी खरी-खरी सुनाई। गुटबाजी अर्कमण्यता सब पर। कांग्रेस का यह दुस्रों साहस ही है कि वह अपना सबसे बड़ा सम्मेलन पूर्ण अधिवेशन (प्लेनरी) 8 और 9 अप्रैल को भाजपा के सबसे मजबूत राज्य गुजरात में कर रही है। उसके शासन वाले तीनों प्रदेश थे। गर्मी के हिसाब से शिमला सबसे पसंदीदा जगह थी। 8 साल बाद वर्ही से पसंदीदा जगह थी। 8 साल बाद वर्ही से कांग्रेस की राजनीतिक वापसी तय हुई थी। 2003 में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष संनियाम गांधी ने वहाँ चिंतन शिविर आयोजित करके सत्ता में वापसी का नया रोड मेप बनाया था। पूरे विषय को साथ लेकर चलने का। उससे पहले पचमढ़ी 1998 में एकला चलो तय किया था। तो अपनी सरकार वाले शहर शिमला में न करके, कर्नाटक, तेलंगाना वाले कांग्रेस शासित राज्यों में भी न जा कर के और बिहार, जहाँ अभी इसी साल विधानसभा चुनाव हैं और सहयोगी दल अरजेडी के साथ वहाँ जीतने की भी अच्छी संभावनाएँ हैं वह सब छोड़कर राहुल गांधी सीधे प्रधानमंत्री मोदीवाले को उनके घर गुजरात जाकर चुनावी दे रहे हैं। यही राहुल की तकत है। अब निर्भार पार्टी पर है कि वह इस अवसर का कितना फायदा उठाया पाती है। पूर्ण अधिवेशन का मुख्य काम होताहोता है देशवासियों में उत्साह भरना। कांग्रेस जिसने आजादी के आन्दोलन का नेतृत्व किया है पूरे देश की इच्छाओं आकांक्षाओं को प्रतिबिम्बित करती रही है। 1920 में कोलकाता से असहयोग अंदोलन का आँदोन किया था



मुम्बई में सीधा अंग्रेजों भारत छोड़े प्रस्ताव पापस कर दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खासा था। जो गांधी जी के साथ संघ और भाजपा के सबसे ज्यादा निशाने पर रहते हैं। खैर तो कांग्रेस के अधिवेशन देश में हमें से क्रान्तिकारी पैगाम लाते रहे हैं। आजादी के बाद देश का सबसे बड़ा आर्थिक फैसला जो अभी भी भारत की अर्थव्यवस्था को संभाले हुए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, उसका फैसला इन्दिरा गांधी ने 1969 में बंगलूरू अधिवेशन में किया था। इतिहास भरा पड़ा है कांग्रेस के अधिवेशनों और देश की तरकीकी का। नई सोच नई हिम्मत देने का और पार्टी के लिहाज से खुद को परिवर्तित करने का। आज कांग्रेस बही नदी से, एक रुका हुआ तालाब बन गई है। राहुल जैसा बिल्कुल न डरने वाला नेता है। उनके जैसे ही साहसी अध्यक्ष। मल्लिकार्जुन खरणे जब अध्यक्ष बने थे तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि वे एक अलग और बड़े व्यक्तित्व के साथ दिखेंगे। मगर खरणे ने एक तरफ साहस के साथ भाजपा और संघ का मुकाबला किया तो दूसरी तरफ पार्टी में समन्वय के साथ काम। इससे अच्छी जोड़ी राजनीति में मिलना मुश्किल है। मगर परिणाम नहीं आ रहे। यह को ही हटाना पड़ेगा। और इन संस्थाओं के रहते उनसे लड़ते उन पर दबाव बनाकर उन्हें गैरकानूनी कामों के रोज परिणाम बताते हुए। और सबसे बड़ी बात अपनी कमियों को दूर करते हुए। यहीं वह बात है जो अहमदाबाद में होना चाहिए। और उसका हल निकलना चाहिए। वहां पहले दिन 8 अप्रैल को कांग्रेस वर्किंग कमेटी पार्टी की सर्वोच्च नीति निर्धारक ईकाई (सीडब्ल्यूसी) की ही मीटिंग है। याद रखना चाहिए कि इससे पहले की दो सीडब्ल्यूसी की मीटिंग दिल्ली और बेलगावी में अध्यक्ष खरणे ने पार्टी की अन्दरूनी समस्याओं की गहरी पड़ताल की और जितनी सुना सकते थे उतनी खरी-खरी सुनाई। गुटबाजी अकर्मण्यता सब पर। और रही सही कसर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अहमदाबाद के फिले महीने ही हुए एक कार्यकर्ता सम्मेलन में यह कहकर पूरी कर दी कांग्रेस में आधे भाजपाई हैं।

अब क्या बचा। डायग्नोस (रोग की पहचान) हो गया। सारी जांच पड़ताल हो गई। मरीज ऑपरेशन टेबल पर आ गया।

मगर लास्ट मिनट में ऑपरेशन करने वाली टीम में एक नया डाक्टर शामिल कर लिया। कांग्रेस यथास्थितिवाद का शिकार हो गई है। वह पार्टी जो देश में परिवर्तन की वाहक मान जाती है। विचार आज भी उसके प्रगतिशील हैं। मगर उन विचारों को आगे बढ़ाने वाला

काम इन दोनों का और इनके साथ जुड़ी टीम का होता है। टुकड़ों-टुकड़ों में कई अच्छे रंग उभरते हैं। मगर पूर्णता में कांग्रेस उठ रही है ऐसा विश्वास नहीं बन रहा है। मोदीजी की कमज़ोरी कांग्रेस का लाभ! समय किसी का नहीं रहता जैसी बातें ठीक हैं। या एक वह वर्ग भी है जो चुनाव आयोग ऐसा है कहकर सारी बात ही खत्म कर देता है। मगर चुनाव आयोग ऐसा है, बाकी संविधानिक संस्थाएं ऐसी हैं कहने से तो चीजें नहीं बदलेंगी। सीधी बात है कि जब तक मेंदी है तब तक चुनाव आयोग और बाकी संस्थाएं ऐसी ही रहेंगी। पहले मोदी दान न एक नया उपर शानदार परिवार राजीव शुक्ला ! सीडब्ल्यूसी का परमानेंट इनवाइट बनाकर। स्थायी आमंत्रित। क्यों? राजीव शुक्ला हिमाचल प्रदेश के प्रभारी थे। उन्हें पिछले दिनों हटा दिया। हटाने के बाद उनकी सीडब्ल्यूसी की सदस्यता खत्म हो गई। वहां वापस लाने के लिए मीटिंग से ठीक पहले उन्हें स्थायी आमंत्रित बना दिया। याद रखिए केवल एक अपाइंटमेंट हुआ है। और प्लेनरी की मीटिंग से ठीक पहले एक होने का मतलब अत्यन्त महत्वपूर्ण। कांग्रेस इसी तरह के मैसेज देती है। सब किए धेर पर पानी। कांग्रेस की भाषा में इसे कहते हैं एडजस्ट हा नगर उन विचारों का जान बढ़ाने वाले संगठन नहीं है। एक उदाहरण देखिए। राहुल गांधी का आज सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? अभी सीपार्टीएस की मुद्राइ कांग्रेस (महाअधिवेशन) ने भौमिका उसका समर्थन कर दिया। जाति से हटकर वह की बात करने वाली देश की सबसे बड़ी लोकपार्टी ने। मतलब मुझ बहुत बड़ा है। जाति गणना का। देश की राजनीति बदल देगा। मगर क्या कांग्रेस उसके लिए अपना संगठन तैयार कर पाएगी? अहमदाबाद में सबसे बड़ा सवाल यही होगा। कांग्रेस के लिए अवसर में चुनौती भी!?

स्वास्थ्य के प्रति करना होगा जागरूक

रमेश सराफ धमारा
स्वास्थ्य हमारे जीवन

स्वास्थ्य हमार जीवन के लए सबसे महत्वपूर्ण है। इसान जब तक स्वस्थ रहता है तब तक उसमें कार्य करने की क्षमता बनी रहती है। जब वह अस्वस्थ होने लगता है तो उसके कार्य करने की क्षमता भी कमजोर पड़ते लगती है। इसलिए हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि पहला सुख मिरायी काया। यानी शरीर स्वस्थ रहने पर ही सबसे पहला सुख मिलता है। आज के दौर में खानपान में लापवाही के चलते अधिकतर व्यक्ति किसी ने किसी बीमारी से ग्रसित रहने लगे हैं। इससे उनके कार्य क्षमता में भी कमी आई है। मनुष्य के अस्वस्थ होने पर उसके उपचार पर पैसे खर्च होते हैं जिससे उसकी अर्थिक स्थिति कमजोर होने लगती है। इसके साथ ही बीमार व्यक्ति का पूरा परिवार भी उसकी बीमारी के चलते तनाव में रहने लगता है। भागम-भाग के दौर वाली आज की जिंदगी में जो व्यक्ति अपना स्वास्थ्य सही रख पाता है। वह कम कमा कर भी सबसे अधिक सुखी रह सकता है। इसलिए हमें सबसे अधिक अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए।

प्रिया देवी

आज दुनिया भर में मनुष्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी दुनिया के देशों को समय-समय पर चितावनी देता रहता है। कुछ वर्ष पूर्व आई कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। मगर वैज्ञानिकों की तपतरता से वैक्सीन निर्माण होने के चलते वह नियंत्रण में आ गई थी। मगर भविष्य में भी ऐसी कोई गरंटी नहीं है कि कोरोना जैसी महामारी फिर नहीं आए। कभी भी कोई नई महामारी आ सकती है। इसलिए हमें हमारे खानपान, रहन-सहन व बातावरण में सावधानी बरतनी चाहिए ताकि हम बेवजह की बीमारियों से बच सकें। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने के लिए प्रति वर्ष 7 अप्रैल को पूरी दुनिया में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने अमेरिका, जापान, और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ भारत को टियर 1 में रखत है। वैश्वक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2024 के अनुसार भारत 42.8 के समग्र सूचकांक स्कोर के साथ 195 देशों में से 66वें स्थान पर है और 2019 से -0.8 का परिवर्तन है। 2021 में दुनिया भर के देशों की स्वास्थ्य प्रणालियों की रैंकिंग के अनुसार, स्वास्थ्य सूचकांक स्कोर के आधार पर भारत 167 देशों में से 111वें स्थान पर था। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार तीन साल की अवस्था वाले 3.88 प्रतिशत बच्चों का विकास अपनी उम्र के हिसाब से नहीं हो सकी है और 46 प्रतिशत बच्चे अपनी अवस्था की तुलना में कम वजन के हैं, जबकि 79.2 प्रतिशत बच्चे एनीमिया से पीड़ित हैं। गर्भवती महिलाओं में एनीमिया 50 रही है। ग्रामीण तबके में देश का अधिकतर आबादी उचित खानपान के अभाव में कुपोषण की शिकार हो रही है। महिलाओं, बच्चों में कुपोषण का स्तर अधिक देखा गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार प्रति 10 में से सात बच्चे एनीमिया से पीड़ित हैं। वहाँ महिलाओं की 36 प्रतिशत आबादी कुपोषण की शिकार है। भारत में इलाज पर अपनी जेब से खर्च करने वाले पीड़ित लोगों की संख्या ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी की संयुक्त आबादी से भी अधिक है भारत की तुलना में इलाज पर अपनी आय का 10 फीसदी से अधिक खर्च करने वाले लोगों का देश की कुल जनसंख्या में प्रतिशत श्रीलंका में 2.9 फीसदी, ब्रिटेन में 1.6 फीसदी, अमेरिका में 4.8 फीसर्दी और चीन में 17.7 फीसदी है। विश्व

के पीछे विश्व स्वास्थ्य संगठन का मकसद दुनियाभर में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। साथ ही साथ सरकारों को स्वास्थ्य नीतियों के निर्माण के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करना। वर्तमान में इस संगठन के बैनर तले 195 से अधिक देश अपने-अपने देश के नामिकों को रोगमुक्त बनाने के लिए प्रयासरत है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने की शुरूआत 1950 से हुई। वैश्विक आधार पर स्वास्थ्य से जुड़े से 58 प्रतिशत बढ़ा है। कहा जाता है कि जिस देश कि चिकित्सा सुविधाएं बेहतर होगी उस देश के लोगों कि औसत आयु उतनी ही अधिक होगी। भारतवासियों को यह जानकर हैरानी होगी कि औसत आयु के मामले में बांग्लादेश भारत से अगे है। भारत में औसत आयु जहां 64.6 वर्ष मानी गई है, वहीं बांग्लादेश में यह 66.9 वर्ष है। इसके अलावा भारत में कम वजन वाले बच्चों का अनुपात 43.5

